भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0 25**

30.11.2015 को उत्तर के लिए

**उत्सर्जन के स्तर में कमी करने हेतु शपथ**

25. **डा. प्रदीप कुमार बालमुचू:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में पेरिस में संपन्न जलवायु परिवर्तन संबंधी 'यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन' की बैठक में उत्सर्जन स्तर में 33-35 प्रतिशत कमी कर पर्यावरण की सुरक्षा करने संबंधी अपनी शपथ प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) और (ख) भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यढांचा कन्वेंशन (यूएनएफसीसी) का एक पक्षकार है। यूएनएफसीसीसी के सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जलवायु परिवर्तन के निराकरण के प्रति अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अभिप्रेत अंशदान (आईएनडीसी) प्रस्तुत करें । तदनुसार, भारत ने अपने आईएनडीसी प्रस्तुत किए हैं जिसमें वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना वर्ष 2030 तक इसकी जीडीपी की कार्बन तीव्रता में 33 से 35 प्रतिशत की कमी की परिकल्पना की गई है ।

भारत के आईएनडीसी में (i) जीवन शैली (ii) स्वच्छतर आर्थिक विकास (iii) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी की उत्सर्जन सघनता में कमी करना (iv) गैर जीवाश्म र्इंधन आधारित विद्युत के भाग में वृद्धि करना (v) कार्बन सिंक (वन) में अभिवृद्धि करना (vi) अनुकूलन (vii) वित्त संसाधन जुटाना (viii) प्रौद्योगिकी अंतरण और (ix) क्षमता निर्माण से संबंधित प्रस्ताव हैं। इसमें विद्युत उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्षेत्रों में सौर पवन, जलीय, जैवमास और नाभिकीय और ऊर्जा दक्षता जैसे नवीकरणीय घटकों के संवर्धन का प्रस्ताव किया गया है ।

\*\*\*\*